नईदुनिया



ब्राजील से भागने में किसने की मदद : फ्लावियो बोल्सोनारो अमेरिका पहुंचे, मार्को रूबियो ने दिया ये जवाब

अटलांटा

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद देश छोड़कर अमेरिका पहुंचे फ्लावियो बोल्सोनारो की यात्रा में कोई मदद नहीं की थी।

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के खिलाफ चुनाव हारने के बाद फ्लावियो बोल्सोनारो बुधवार को मियामी पहुंचे थे। इससे एक दिन पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि चुनाव में हार के बाद बोल्सोनारो और उनके परिवार को अमेरिकी वीजा दिया जाएगा। यह चुनाव कड़ा मुकाबला था और लैटिन अमेरिका में रूढ़िवादी दलों की चुनावी सफलता के रुझान से अलग रहा।

रूबियो बोले- राष्ट्रपति ने दी देश में प्रवेश की अनुमति - जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए अटलांटा पहुंचे रूबियो ने पत्रकारों से कहा, हमने किसी भी तरह की मदद नहीं की। उन्होंने कहा, हमें जानकारी मिली थी कि वह अमेरिका पहुंच गए हैं। उनके पास पहले से वीजा था और राष्ट्रपति ने उन्हें देश में प्रवेश की अनुमति देने का फैसला किया। रूबियो ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी सरकार उनकी यात्रा से जुड़े किसी भी कदम में सीधे तौर पर शामिल नहीं थी।

रूबियो ने बताया कि अटलांटा में शुक्रवार और शनिवार को उनकी ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि नवंबर में फ्रांस में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भी उनकी ब्राजील के अधिकारियों से बातचीत होने की उम्मीद है।

फ्लावियो बोल्सोनारो ने क्यों छोड़ा ब्राजील - फ्लावियो बोल्सोनारो ने चुनाव में हार स्वीकार नहीं की है। उन्होंने बिना कोई सबूत दिए चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। उनके पिता और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने भी 2022 में लूला से मिली हार को स्वीकार नहीं किया था। तख्तापलट की कोशिश के मामले में वह 27 साल की सजा काट रहे हैं।

चुनाव में फ्लावियो को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अप्रत्यक्ष समर्थन हासिल था। ब्राजील में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, मनी लान्ड्रिंग और कर चोरी के मामलों की जांच चल रही है। पुलिस ने उन्हें देश छोड़कर भागने का जोखिम मानते हुए पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था।

खुद को बताया ब्राजील का असली निर्वाचित राष्ट्रपति - रियो डी जेनेरियो से सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर लाइव प्रसारण के दौरान फिर दावा किया कि उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। ब्राजील की नई संसद का कार्यकाल एक फरवरी से शुरू होगा और इसके बाद वह अपनी सीनेटर की सीट गंवा देंगे। 45 वर्षीय बोल्सोनारो ने बुधवार को लिखे एक पत्र में खुद को ब्राजील का वास्तविक निर्वाचित राष्ट्रपति बताया था। हालांकि, बाद में उन्होंने इस दावे को नरम करते हुए खुद को नेता कहा। उन्होंने अपनी तुलना कई अन्य हस्तियों के साथ फ्रांस के चार्ल्स डी गाल से भी की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डी गाल ने लंदन से फ्रांस में नाजी कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया था।

न्यूज ब्रीफ

बांग्लादेश में बस हादसा, राहगीर की मौत, जमात के 30 कार्यकर्ता घायल



ढाका (बांग्लादेश)। देश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से के खुलना अंतर्गत सतखीरा के पाटकेलगहाटा में हुए बस हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई और जमात-ए-इस्लामी के कम से कम 30 कार्यकर्ता घायल हो गए। बस में सवार ये कार्यकर्ता सड़क किनारे एक खाई में जा गिरे। यह हादसा करीब 8:30 बजे खुलना-सतखीरा राजमार्ग के चाराबोतोला इलाके में हुआ। जमात कार्यकर्ता खुलना से 11 दलीय गठबंधन के रोड मार्च से लौट रहे थे। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की पहचान 65 वर्षीय अब्दुल खालिक मोल्लाह के रूप में हुई है। वह पाटकेलगहाटा के काशियाडांगा गांव में रहते थे। उनके पड़ोसी रिपन मुल्ला ने बताया कि खुलना में रोड मार्च में शामिल होने के बाद जमात कार्यकर्ता बस से सतखीरा लौट रहे थे। जब अब्दुल खालिक चाराबोतोला चौराहे के पास सड़क पार कर रहे थे तभी बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बस सड़क किनारे एक खाई में जा गिरी। सतखीरा जमात के महासचिव अजीजुर रहमान ने कहा कि जब बस रोड मार्च से लौट रही थी, तो बुजुर्ग अचानक बस के सामने आ गए। उन्होंने कहा, उन्हें बचाने की कोशिश में हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को ले जा रही बस सड़क से उतरकर किनारे की खाई में जा गिरी, जिससे कम से कम 30 कार्यकर्ता घायल हो गए।

नेपाल के डोल्पा में भारी बर्फबारी, 6 भारतीय पर्यटक लापता



काठमांडू। नेपाल के डोल्पा जिले में भारी बर्फबारी के बीच शे-फोक्सुंडो झील की ओर जा रहे छह भारतीय पर्यटक लापता हो गए हैं। लापता पर्यटकों में दो महिला और चार पुरुष शामिल हैं। । नुमला पास और बगला पास के इलाके में उनसे संपर्क टूट गया । ये दोनों दर्रे शे-फोक्सुंडो के वार्ड नंबर 4 और 8 के बीच स्थित हैं। डोल्पा की मुख्य जिला अधिकारी जुनु हमाल ने बताया कि पर्यटक धो से फोक्सुंडो झील की ओर लौट रहे थे, तभी वे बर्फ में फंस गए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने उन्हें पहाड़ पार करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में आगाह किया था, लेकिन वे आगे बढ़ गए और अब उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। शे-फोक्सुंडो गांवपालिका के अध्यक्ष धावा साम्दुक गुरूग के अनुसार, वार्ड नंबर 4 और 8 के बीच स्थित दर्रों में मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। संचार सुविधा नहीं होने के कारण पर्यटकों की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाना मुश्किल हो रहा है। डोल्पा के पुलिस उपाधीक्षक अनिल राज गिरी ने बताया कि इन पर्यटकों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि तलाश और बचाव अभियान के लिए संबंधित निकायों से हेलीकाप्टर की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।

पाकिस्तान ने चेताया- आतंकवाद पर अफगानिस्तान की निष्क्रियता बर्दाश्त नहीं



इस्लामाबाद (पाकिस्तान)। संघीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने काबुल कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि तालिबान नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहा है। वह तनावपूर्ण संबंधों के असल कारण यानी अफगानिस्तान से चल रहे आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म करने के बजाय इस्लामाबाद की नीतियों को दोष दे रहा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी, आतंकवाद पर अफगानिस्तान की निष्क्रियता अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान का रुख एकदम साफ है। आतंकवाद अस्वीकार्य है। अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।इस्लामाबाद सीमा पार मौजूद उन आतंकवादी ठिकानों को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हैं।पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पैदा होने वाले खतरों को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखता है, चाहे ये खतरे कहीं से भी आ रहे हों। मंत्रालय ने कहा, इस स्थिति के लिए अफगान तालिबान शासन जिम्मेदार है। मंत्रालय ने काबुल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अफगान तालिबान अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान की सुरक्षा को अफगान तालिबान की निष्क्रियता, टालमटोल या गलत प्राथमिकताओं का बंधक नहीं बनने दिया जाएगा।

एस.जयशंकर : क्वाड देशों में चुनने की आजादी जरूरी, सप्लाई चेन और आर्थिक सुरक्षा पर विदेश मंत्री

अटलांटा

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने क्वाड के लिए चुनने की स्वतंत्रता, मजबूत सप्लाई चेन और गैर-बाजार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई को मुख्य प्राथमिकता बताया। इसके साथ ही, उन्होंने इस समूह के एजेंडे के लिए एक अधिक समकालीन और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की।



अटलांटा में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद, एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में जयशंकर ने उन प्रमुख मुद्दों का जिक्र किया, जिन पर उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और आस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ चर्चा की थी।

जयशंकर ने कहा समूह की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना, समृद्धि को बढ़ावा देना और पसंद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना हमारी निरंतर प्रतिबद्धताएं हैं। उन्होंने टेक्नोलाजी, महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत सप्लाई चेन बनाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहतर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

गैर-बाजार प्रथाओं का भी किया जिक्र

जयशंकर ने चर्चा के दौरान उठाई गई प्राथमिकताओं में इंडो-पैसिफिक में गैर-बाजार प्रथाओं का मुकाबला करने और बढ़ते आर्थिक दबावों को भी शामिल किया। हालांकि, उनकी पोस्ट में किसी देश का नाम नहीं लिया गया और न ही यह बताया गया कि किन विशिष्ट प्रथाओं की बात हो रही है।

क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, उन्होंने आतंकवाद-रोधी, समुद्री सुरक्षा और क्षमता निर्माण से जुड़े मौजूदा समझौतों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया, ताकि मजबूती बढ़ाई जा सके और शांति व स्थिरता को समर्थन मिले।

एआई को लेकर क्या चर्चा हुई

मंत्रियों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए 85 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक की तकनीकी और वित्तीय सहायता देने की इच्छा जताई। इसमें क्वाड एआई एक्सेलेरेटर के माध्यम से दी जाने वाली मदद भी शामिल है। विज्ञप्ति में सुपर इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया गया है, जिसके साथ एक फुटनोट में स्पष्ट किया गया है कि यह शब्द भारत, आस्ट्रेलिया और जापान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है।

मंत्रियों ने भारत और आसियान देशों में कचरे से महत्वपूर्ण खनिज निकालने की सुविधाओं के लिए वाशिंगटन द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डालर देने के वादे का स्वागत किया। यह राशि केवल भारत के लिए नहीं है।

ये चारों साझेदार देश, इलेक्ट्रानिक कचरे और कबाड़ से खनिज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम की जा सके। वे रीसाइकल होने वाली सामग्रियों को एक देश से दूसरे देश भेजने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के तरीकों पर भी विचार करेंगे। समुद्री सहयोग के तहत, चारों देशों के प्रतिनिधियों ने 25 सितंबर से 7 अक्तूबर के बीच चेन्नई से पर्थ तक भारतीय तटरक्षक बल के एक गश्ती जहाज पर यात्रा की।

क्या है क्वाड

क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया शामिल हैं। इनका सहयोग समुद्री और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण व उभरती प्रौद्योगिकियों, तथा मानवीय सहायता और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है।

इसके साथ ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत ने जी20 को बताया कि ऊर्जा आपूर्ति का राजनीतिकरण बहुत हानिकारक है। ऊर्जा की कमी का सबसे बुरा असर ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) पर पड़ रहा है। उन्होंने जी20 समूह से इस समस्या को समझने और स्वीकार करने का आग्रह किया। अटलांटा में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद, भारतीय पत्रकारों के एक समूह से बात करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बैठक को बहुत ही सार्थक, बहुत खुली और काफी जीवंत जी20 बैठक बताया।

ईरान की होर्मुज को खोलने पर कतर से वार्ता, कहा- अमेरिका पहले शर्त माने



तेहरान (ईरान)

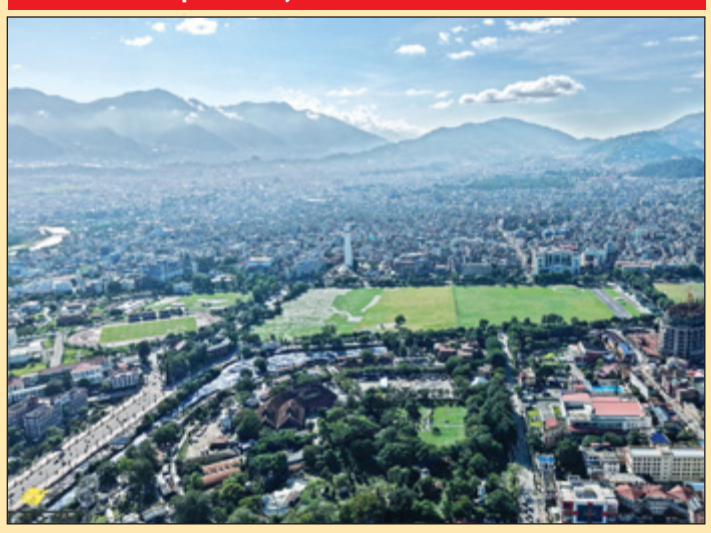
मध्य पूर्व में तनाव का प्रमुख कारण बन चुके होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने को लेकर कतर के मध्यस्थों के साथ ईरान के शीर्ष नेताओं की बातचीत चल रही है।

ईरान ने कतर को साफ कर दिया है कि अमेरिका को पहले उसकी शर्तें मानने को तैयार होना होगा। ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अगर अमेरिका अगर शर्तें मान लेता है तो होर्मुज जलडमरूमध्य को दो दिन में फिर से खोल दिया जाएगा।

अल जजीरा और इरना की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराघची ने कतरी मध्यस्थों के चल रही बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को दो दिन में फिर से खोलने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि अमेरिका को उनकी सभी मांगें माननी होंगी। उधर, ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेजाई का कहना है कि उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पत्र को देखा है। इसके अध्ययन से साफ है कि वाशिंगटन के रुख में पूरी तरह से बदलाव आया है। उन्होंने इस बदलाव को एक सकारात्मक संकेत बताया है।

इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अपने सैन्य कमांडरों को निर्देश दिया है कि वे अमेरिका और इजराइल की ओर से आने वाले किसी भी संभावित खतरे का बिना किसी भौगोलिक सीमा के, तत्काल और प्रभावी जवाब दें। सशस्त्र बलों के चीफ आफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि खामेनेई के निर्देश के बाद ईरानी बल तैयार हैं। मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने बताया कि कमांडर-इन-चीफ अयातुल्ला सैयद मोजतबा हुसैनी खामेनेई के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को दिए गए आदेश के बाद ईरानी सशस्त्र बलों ने अपने एजेंडे में दुश्मन के ठिकानों और संपत्तियों की एक नई सूची शामिल की है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक क्रांति के नेता का समझदारी भरा और निर्णायक नेतृत्व सशस्त्र बलों के कमांडरों और सभी सदस्यों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। अब्दुल्लाही ने कहा कि सशस्त्र बल किसी भी तरह की आक्रामकता का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने कमांडर-इन-चीफ और देश को भरोसा दिलाया कि वे अंतिम सांस तक देश की रक्षा के लिए अडिग खड़े रहेंगे।

चक्रवात अर्नब पड़ा कमजोर, नेपाल में मौसम धीरे-धीरे हो रहा सामान्य



काठमांडू। पश्चिमी नेपाल के आसपास स्थित कम दबाव वाले क्षेत्र का प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। यह क्षेत्र चक्रवात अर्नब का अवशेष है। इसके प्रभाव में कमी आने के साथ ही मौसम में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार, फिलहाल लुम्बिनी प्रदेश सहित देश के पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए हुए हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में आंशिक रूप से बादल लगे हैं। बागमती, गंडकी, लुम्बिनी और कर्णाली प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो रही है। महाशाखा के मुताबिक, देशभर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हिमालयी और पहाड़ी क्षेत्रों के एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। देशभर में मौसम आंशिक रूप से बादलयुक्त रहेगा। गंडकी, कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमालयी और पहाड़ी क्षेत्रों के एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है।

इस्राइल जनादेश : पीएम चुनने का विधेयक ला सकता है विपक्षी दल, बदू महिलाओं ने कैसे पलटा नेतन्याहू का चुनावी पासा

यरूशलम



उम्म खालिद फतून पिछले साल युद्ध पीड़ितों के लिए बने एक यहूदी-अरब सहायता केंद्र में स्वयंसेवा करके लौटीं तो उन्होंने देखा कि बुलडोजर अजारनुग गांव में उनके बेटे के घर को ढहा रहे थे। पुलिस की निगरानी में आई टीम ने घर पर बुलडोजर चलाने से पहले फर्नीचर या सोलर पैनल तक हटाने का मौका नहीं दिया।

अब, इस हफ्ते जब फतून को मौका मिला तो उन्होंने अपनी नाराजगी का जवाब इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ मतदान करके दिया। उनका सीधा निशाना राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-ग्विर थे जिन्होंने फलस्तीनी और अरब समुदाय के लोगों के घरों को व्यापक स्तर पर ढहाने का आदेश दिया था। फतून कहती हैं, बेन-ग्विर को सत्ता से बाहर करना ही मेरा एकमात्र मकसद था। बदू समुदाय में ऐसा एक भी परिवार नहीं है जो हमारे खिलाफ उसके अभियानों से पीड़ित न हुआ हो। चुनाव से कुछ हफ्ते पहले फतून ने बदू महिलाओं को उनके अधिकारों और राजनीतिक ताकत के प्रति जागरूक करने के लिए जमीनी स्तर पर बाकायादा अभियान शुरू किया। इसके शानदार नतीजे भी दिखे, और चुनाव में दक्षिणी नेगेव इलाके के कुछ बदू गांवों में मतदान प्रतिशत तीन गुना तक बढ़ गया।

हमें अपने हर वोट की ताकत झोंकनी होगी - अल-नश्मियात अभियान का नेतृत्व करने वाली वकील हनान अलसनाह ने कहा, वर्षों के हिंसक शासन ने इस रूढ़िवादी समुदाय में बदलाव का दरवाजा खोल दिया है। हमने महिलाओं से कहा कि भले सभी पुरुष वोट दें फिर भी समुदाय का आधा हिस्सा ही होंगे। आपको अपने हर वोट की ताकत चाहिए, क्योंकि बेन-ग्विर के पास बहुत ताकत है।

62% से 93% तक दर्ज की गईवोटिंग - बदू समुदाय इस्राइली संसद नेसेट में अरब पार्टियों को 19 सीटें दिलाकर किंगमेकर की भूमिका में ला दिया। बदू समुदाय में सबसे कम मतदान 62% रहा, जबकि सबसे ज्यादा मतदान 93% दर्ज किया गया। उनके उत्साह से ही रआम पार्टी को चुनावी अनुमानों से काफी अधिक सफलता मिली।

विपक्षी दल सीधे पीएम चुनने का ला सकता है विधेयक - इस्राइल में सरकार गठन में राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए विपक्षी गुट अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर रहे बिना अल्पमत सरकार बनाने के लिए सीधे प्रधानमंत्री चुनने से संबंधित विधेयक लाने पर विचार कर रहा है। टाइम्स आफ इस्राइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रस्ताव लागू होने पर मतदाता सरकार से अलग सीधे पीएम पद के लिए वोट डाल सकेंगे।

ईरान पर नए सैन्य हमले की तैयारी: डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर की बात, संभावित कार्रवाई की चर्चा

वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब वाशिंगटन ईरान के खिलाफ नए सिरे से सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं का आकलन कर रहा है। द वाल स्ट्रीट जर्नल ने इस बातचीत से परिचित सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है।

क्या ईरान पर हमला करेगा अमेरिका - अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सप्ताह की शुरुआत में व्हाइट हाउस में हुई एक बैठक के बाद दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत हुई। इस बैठक में ट्रंप ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने के संभावित विकल्पों पर चर्चा की थी। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर विभिन्न रणनीतिक विकल्पों पर विचार कर रहा है। हालांकि, बातचीत में किन मुद्दों पर विस्तार से



चर्चा हुई और किसी सैन्य कार्रवाई को लेकर क्या फैसला लिया गया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत लगातार जारी है और इसमें कोई रुकावट नहीं आई है। हालांकि, उन्होंने बातचीत की समयसीमा या अब तक हुई प्रगति के बारे में कुछ भी बताने से इनकार किया। रुबियो ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आगे सैन्य कार्रवाई को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया है।

विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या कहा - जार्जिया में जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के समापन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रुबियो ने कहा कि अमेरिका अब भी ऐसे कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है, जो उसकी बुनियादी सुरक्षा चिंताओं को दूर कर सके। उन्होंने ईरान पर वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाकर समुद्री क्षेत्र में आक्रामक गतिविधियां करने और मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने वाले सशस्त्र समूहों का समर्थन करने का आरोप भी लगाया।

रुबियो ने कहा, कई स्तरों पर बातचीत चल रही है और यह कभी रुकी ही नहीं। कुछ मामलों में सीधे तौर पर, जबकि ज्यादातर मामलों में मध्यस्थों के जरिए सक्रिय बातचीत हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री से पूछा गया था कि सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने से पहले वाशिंगटन कूटनीतिक प्रयासों को कितना समय देना चाहता है। इस पर उन्होंने कहा कि बातचीत की समयसीमा तय करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। उन्होंने यह बताने से भी परहेज किया कि किसी अंतिम समझौते के करीब पहुंचा जा चुका है या नहीं। रुबियो ने कहा, मैं न तो इन वार्ताओं की प्रगति पर कोई टिप्पणी करूंगा और न ही इनकी समयसीमा बताऊंगा। हालांकि, इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर कोई कूटनीतिक समाधान निकलता है तो अमेरिका इसके लिए तैयार रहेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर क्या बोला अमेरिका - रुबियो ने जोर देकर कहा कि किसी भी समझौते में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा होनी चाहिए। साथ ही, उन चिंताओं का समाधान भी जरूरी है, जिनकी वजह से मौजूदा संकट पैदा हुआ है। उन्होंने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को उसके समर्थन को अमेरिका की प्रमुख चिंताओं में शामिल बताया।